

पहले निडर बनो फिर लीडर बन जाओगे

'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन का दूसरा एपिसोड, देशभर से आए छात्रों से पीएम ने की मुलाकात

नई दिल्ली, 09 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देशभर से आए छात्रों से मुलाकात की.

पीएम मोदी कोयंबटूर से छत्तीसगढ़ पहुंचे और बच्चों से बात की. इसके बाद पीएम गुवाहाटी के अटलक्ष्मी पहुंचे. पीएम ने कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने में करें. पीएम ने बच्चों को पढ़ने के साथ, लिखकर प्रैक्टिस करने की सलाह दी. साथ ही बच्चों से कहा कि पहले निडर बनो फिर लीडर बन जाओगे. इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ नौकरी के लिए



जिंदगी नहीं जीनी चाहिए. वहीं पढ़ाई और जुनून के बीच संतुलन बनाना चाहिए. पीएम मोदी ने छात्रों को रिलेक्स करने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि हमें

केवल किताबों में व्यस्त नहीं रहना चाहिए; मस्कराना, हंसना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए. पर्याप्त नींद लेने से आप प्रफुल्लित रहेंगे. नए-नए विचार आएंगे.

सुपरटेक प्रोजेक्ट पूरे करेगा एनबीसीसी

कोर्ट ने एनबीसीसी के अधिदेश को बरकरार रखा



नई दिल्ली, 09 फरवरी. भारत के रियल एस्टेट और अवसरंचना क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के उस निर्णय को बरकरार रखा है.

जिसके तहत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनबीसीसी (ईडिया) लिमिटेड को सुपरटेक लिमिटेड की 16 अटकों हुई आवासीय परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए अधिकृत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की अभिप्रेष्टि इन परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में एनबीसीसी की भूमिका को अंतिम कानूनी निश्चितता प्रदान करती है और

इनके निष्पादन एवं पूर्णता के लिए एक स्पष्ट और बाध्यकारी ढांचा स्थापित करती है। यह निर्णय देश के सबसे बड़े संकटग्रस्त रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में से एक के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम है.

एस्टीन से संपर्क के खुलासे के बाद नॉर्वे की राजदूत का इस्तीफा

ओस्लो, 09 फरवरी. नॉर्वे की जॉर्डन में राजदूत तथा इराक के लिए भी मान्यता प्राप्त मोना जूल ने अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एस्टीन के साथ संपर्कों से जुड़े खुलासों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.



नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ आइडे ने जूल के इस्तीफे को सही और आवश्यक बताया हुए कहा कि दोषसिद्ध यौन अपराधी के साथ उनका संपर्क निर्णायक चूक को दर्शाता है और इससे इस पद के लिए आवश्यक भरोसे के स्तर को बहाल करना कठिन हो गया था. मंत्रालय के अनुसार, जूल को पिछले सप्ताह उनके कार्य दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था, जबकि मंत्रालय उनके एस्टीन से संबंधों और संपर्कों को समीक्षा कर रहा था. मंत्रालय ने कहा कि जूल के इस्तीफे के बाद भी आंतरिक जांच जारी रहेगी, जिसमें सेवा के दौरान और सेवा से बाहर राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. मंत्रालय

जापान : चुनाव में एलडीपी की एकतरफा जीत

टोक्यो, 09 फरवरी. जापान में रिविवा को हुए आम चुनाव में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) और जापान इन्वेंशन पार्टी (जेआईपी) के गठबंधन ने निचले सदन में दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल कर लिया है. सरकारी प्रसारक एनएचके ने



सोमवार तड़के यह जानकारी दी. एनएचके के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन ने कुल 352 सीटें जीतीं, जो निचले सदन में पारित लेफिन उच्च सदन (हाउस ऑफ

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है. एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

एलडीपी के पास चुनाव से पहले 198 सीटें थीं. पार्टी ने अपने दम पर ही 465 सदस्यों वाले निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया और कुल 316 सीटें जीतीं. वहीं, जूनियर सहयोगी जेआईपी के लिए परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहे. पार्टी ने निचले सदन में अपनी पूर्व 34 सीटों के मुकाबले केवल दो सीटों की बढ़ोतरी की है.

कार्डिसलर्स) द्वारा खारिज किसी विधेयक को पुनः पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक है.

मणिपुर से भारी मात्रा में हथियार बरामद

इंफाल. सुरक्षा बलों ने मणिपुर के विभिन्न जिलों में चलाये गये अलग-अलग अभियानों के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है. सुरक्षा बलों ने नोनी जिले के नुंगब पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लेंगोलों और ताईखों के सामान्य क्षेत्रों से रिविवा को हथियार और गोला-बारूद बरामद किये. बरामद वस्तुओं में मैगजीन के साथ एक 7.62 मिमी एके-47 राइफल, मैगजीन के साथ एक यूएस कार्बाइन एम2, मैगजीन के साथ एक. 22 पिस्तौल, एक डीजेआई ड्रोन, चार 8 मिमी ब्लैंक राउंड, 5.56 मिमी गोला-बारूद 17 राउंड, 7.62 मिमी एके-47 की 39 गोलियां, आठ 9 मिमी कार्बाइन बॉल गोलियां, नौ 7.62 मिमी एसएलआर बॉल राउंड, अन्य हथियार शामिल हैं.

ममता को सुको से झटका

बंगाल के डीजीपी हलफनामा दाखिल करें: सुप्रीम कोर्ट
एसआईआर में रुकावट नहीं करें राज्य

नई दिल्ली, 09 फरवरी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों में चल रही मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिफ रिवीजन (एसआईआर) में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कुछ अराजक तत्वों की ओर से निर्वाचन आयोग के नोटिस जलाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इस दलील पर गौर किया कि अब तक उपद्रवियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह संदेश जाना चाहिए कि देश का संविधान सभी राज्यों पर लागू होता है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण संबंधी अंतिम निर्णय हमेशा मतदाता सूची अधिकारियों की ओर से ही लिए जाएंगे.

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इसी तरह के वॉटर रिवीजन एक्ससाइज नहीं किए जा रहे हैं और ईसीआई को बार-बार दिए गए रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं मिला है. इन दलीलों पर जवाब देते हुए सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट एक व्यावहारिक समाधान ढूँढेगा.

नहीं की गई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह संदेश जाना चाहिए कि देश का संविधान सभी राज्यों पर लागू होता है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण संबंधी अंतिम निर्णय हमेशा मतदाता सूची अधिकारियों की ओर से ही लिए जाएंगे.

तुर्की में एक टन से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त, 144 तस्कर गिरफ्तार

इस्तांबुल. तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने सोमवार को घोषणा की कि तुर्की पुलिस ने पिछले 10 दिनों में देश भर में चलाये गये अभियानों में 1.24 टन नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 144 संदिग्धों को हिरासत में लिया है. श्री येरलिकाया ने एक्स पर एक बयान में कहा कि इन छात्रों के दौरान पुलिस ने 18.3 लाख नशे की गोलियां भी जब्त कीं. मंत्री ने बताया कि 24 प्रांतों में चलाए गये इन अभियानों का समन्वय मुख्य सरकारी वकीलों और एंटी-नारकोटिक्स इकाइयों ने किया था.

कार्यालय स्थानांतरित करने सरकार आजाद

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 09 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर रोक लगायी गयी थी.

न्यायालय ने कहा कि किसी संस्था के मुख्यालय का स्थानांतरण नीति से जुड़ा विषय है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश अत्यंत सीमित होती है. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति

न्यायालय परिसर में हिंसा की घटनाएं गुंडा राज

उच्चतम न्यायालय ने अदालत परिसर के भीतर हिंसा की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए इसे गुंडा राज करार देते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से विधि के शासन की विफलता है. न्यायालय दिल्ली के तीस हजारी अदालत परिसर के भीतर अधिवक्ता पर हुए हमले के संबंध में सुनवाई कर रहा था. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ को ऐसी घटना से अवगत कराया जो कथित तौर पर सात फरवरी को तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हरजीत सिंह पाल की अदालत के सामने हुई थी.

जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि किसी संस्था के मुख्यालय को

स्थानांतरित करना एक नीतिगत निर्णय है.

पश्चिम रेलवे - रतलमा मंडल

ई-निविदा सूचना
वरीष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलमा मंडल, पश्चिम रेलवे भारत के राष्ट्रपति की ओर से नियुक्ति कार्य हेतु IREPS पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करते हैं: निविदा क्रमांक: EL/TRD/58/2025-26/22, दिनांक 06.02.2026. कार्य का नाम: TRD Work in connection with electrification work between Chanderiya (CNA)-Ajmer (All). अनुमानित लागत: रु. 5,65,37,300/- (बिना शर्तों के). 4.32,700/-, सामान्य अवधि: 12 Months. निविदा दस्तावेज की राशि: Nil. ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय: 02.03.2026 at 15:00 hrs. ऑफर की वैधता: 60 days from the date of opening. वेबसाइट: www.ireps.gov.in. नोटिस बोर्ड: वरीष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलमा मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने। SPAN/13/1/1450
दो नॉक को: facebook.com/WesternRly

न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त अमड़ोरा टप्पा कार्यालय अमड़ोरा तहसील सदरदारपुर, जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक / 7020 / रीडर-1 / 2026, अमड़ोरा दिनांक 04/02/2026
-- विज्ञप्ति --
एतद् विज्ञप्ति द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है, कि आवेदक कार्यपालनवर्ती ओएसपी नहर संभंग म.प्र.शासन नर्मदाघाटी विकास धामनोद जिला धार कलेक्टर महोदय, जिला धार के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0216 / अ-20 (3 / 2024-25 के निर्देशानुसार ग्राम सेमलीपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 154, 244, 297, 467 रकबा क्रमशः 2.194, 1.62, 0.951, 0.261 भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) क्षेत्र सदरदारपुर के माध्यम से जांच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है।
उक्त वर्णित शासकीय भूमि आवंटन के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में निम्न पेशी दिनांक 11/02/2026 या इसके पूर्व स्वयं अथवा मार्फत अधिभाषक के लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जारी की गई।
यह विज्ञप्ति आज दिनांक : 4/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से नायब तहसीलदार, वृत्त अमड़ोरा तहसील सदरदारपुर
G25620/25

कार्यालय-सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)

पत्र क्रमांक- 50 / री-1 / भू-अर्जन / 2026, धरमपुरी, जिला- धार (म.प्र.)
धरमपुरी, दिनांक 13/01/2026
रा.प्र.क्र. - 0101 / बी-121 / 2025-26

अधिसूचना :-
प्रारंभ - 'ख'
नियम - 5 का उपविभाग (2)
आएव, राज्य सरकार को लोकोक्ति में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि धार उच्च माहको संविधि परियोजना के अंतर्गत तहसील धरमपुरी जिला धार के 13764 हेक्टर री. सी. ए. क्षेत्र में पम्प श्रवण क्रमांक- 01 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन बिछाने हेतु 'ग्राम-बागड़ीपुर, प.ह.नं.- 47/98, र. नि. सं.- 01, धरमपुरी, तहसील - धरमपुरी, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्रो, नर्मदा विकास संघ क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाई जाए। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।
आएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डकट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डकट बिछाने जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमपुरी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आवेग भेज सकते।
-- अनुसूची --

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर/घर में)			
धार	धरमपुरी	ग्राम-बागड़ीपुरा, प.ह.नं.- 47/98,	32	0.011			
			33/2/3	0.003			
			33/2/2	0.041			
			33/2/1/2	0.016			
			33/2/1/1	0.050			
			30/2	0.042			
			30/4/2	0.019			
			30/1	0.029			
			27/2	0.086			
			28/1	0.008			
धार	धरमपुरी	ग्राम-बागड़ीपुरा, प.ह.नं.- 47/98,	27/3	0.035			
			27/1	0.026			
			19/2/2	0.049			
			19/1	0.040			
			246/1	0.029			
			246/2	0.036			
			245/1/2	0.010			
			245/3	0.029			
			245/2	0.005			
			244/1/2	0.043			
धार	धरमपुरी	ग्राम-बागड़ीपुरा, प.ह.नं.- 47/98,	244/2/1/3	0.002			
			244/2/1	0.042			
			244/3/1	0.031			
			23	0.682			
			कुल योग निजी भूमि				23
			उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-				248
							0.005
							259
							0.024
							260
				0.005			
				261			
				0.005			
कुल योग शासकीय भूमि				04			
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)				27			
				0.721			

(प्रमोद सिंह गुर्जर) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमपुरी, जिला- धार (म.प्र.)